

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

02.04.2025 के

तारांकित प्रश्न सं. 454 का उत्तर

रेलवे से संबंधित लंबित प्रस्ताव

\*454. श्री वामसि कृष्णा गद्दामः

श्री के. सी. वेणुगोपालः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) नई लाइनें बिछाने, दोहरीकरण और विद्युतीकरण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त तथा विगत पांच वर्षों से रेलवे के पास लंबित रेल परियोजना प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार और परियोजनावार ब्यौरा क्या है;
- (ख) अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवंटित धनराशि का राज्यवार और परियोजनावार ब्यौरा क्या है;
- (ग) इन रेल परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण लागत में होने वाली वृद्धि का ब्यौरा तथा ऐसी रेल परियोजनाओं के पूरा होने की समय-सीमा क्या है;
- (घ) क्या सरकार को तेलंगाना के मंचेरियल, मंदमारि और बेल्लमपल्ली स्टेशनों पर एक्सप्रेस और सुपरफास्ट रेलगाड़ियों के ठहराव के संबंध में तेलंगाना राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा अनुरोध पर कार्रवाई करने की समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

दिनांक 02.04.2025 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 454 के भाग (क) से (ड) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ड): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है, न कि राज्य-वार/केन्द्र शासित प्रदेश-वार/जिला-वार क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम स्थान संपर्कता, अनुपलब्ध कड़ियों और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों में बढ़ोतरी, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्वों आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है जो चालू परियोजनाओं के थो-फॉरवर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलवे, मंडल कार्यालय आदि सहित विभिन्न स्तरों पर रेल परियोजनाओं/निर्माण कार्यों के लिए, देशभर में राज्य सरकारों, संसद सदस्यों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी आवश्यकताओं, संगठनों/रेल उपयोगकर्ताओं आदि के आधार पर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के प्रस्ताव/अनुरोध/सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। चूंकि ऐसे प्रस्तावों/शिकायतों/सुझावों की प्राप्ति एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः ऐसे अनुरोधों का केंद्रीकृत संग्रह नहीं रखा जाता है। तथापि, इनकी जांच की जाती है तथा उचित और व्यवहारिक पाए जाने पर समय-समय पर कार्रवाई की जाती है।

वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, भारतीय रेल में लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए की लागत और 9,605 कि.मी. कुल लंबाई की कुल 245 परियोजनाओं (46 नई लाइन, 18 आमान परिवर्तन और 181 दोहरीकरण) को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 72,818

कि.मी. कुल लंबाई के 1033 सर्वेक्षण कार्यों (313 नई लाइन, 13 आमान परिवर्तन और 707 दोहरीकरण) को स्वीकृति दी गई है।

दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में 44,488 किलोमीटर कुल लंबाई की 488 रेल अवसंरचना परियोजनाएँ (187 नई लाइन, 40 आमान परिवर्तन और 261 दोहरीकरण), जिनकी लागत लगभग 7.44 लाख करोड़ रुपए है, योजना/अनुमोदन/निर्माण चरण में हैं, जिनमें से 12,045 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक लगभग 2.92 लाख करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। इसका सारांश निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई नई लाइन/आमान परिवर्तन/दोहरीकरण (कि.मी. में)	मार्च 2024 तक कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2024 तक कुल व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	187	20199	2855	160022
आमान परिवर्तन	40	4719	2972	18706
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	261	19570	6218	113742
कुल	488	44,488	12,045	2,92,470

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान रेल विद्युतीकरण के लिए 6,150 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

भारतीय रेल में नए रेलपथों को कमीशन करने/बिछाने का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथों की औसत कमीशनिंग
2009-14	7,599 कि.मी.	4.2 कि.मी. प्रतिदिन
2014-24	31,180 कि.मी.	8.54 कि.मी. प्रतिदिन (2 गुना से अधिक)

लागत, व्यय और परिव्यय सहित रेल परियोजनाओं के क्षेत्रीय रेल वार ब्यौरे भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं।

किसी भी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, अतिलंघनकारी जन सुविधाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना स्थल (स्थलों) के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु अवस्थाओं के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

### तेलंगाना

तेलंगाना में रेल परियोजनाएँ भारतीय रेल के दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे जोनों के अंतर्गत आती हैं।

दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, तेलंगाना राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुल 2,298 कि.मी. लंबाई को कवर करने वाली 32,946 करोड़ रुपए की लागत की 20 परियोजनाएँ (07 नई लाइन और 13 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निर्माण के चरण में

हैं, जिनमें से 474 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक 9,958 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। इसका सारांश निम्नानुसार है:

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2024 तक व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	7	997	245	4432
दोहरीकरण	13	1301	230	5526
कुल	20	2298	474	9958

वर्ष 2014 से, बजट आवंटन और परियोजनाओं की तदनुरूपी कमीशनिंग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तेलंगाना राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले अवसंरचना संबंधी और अन्य निर्माण कार्यों के लिए वार्षिक बजट आवंटन निम्नानुसार है:

वर्ष	बजट परिव्यय	2009-14 के दौरान औसत वार्षिक आवंटन के संदर्भ में वृद्धि
2009-2014	886 करोड़ रु. प्रति वर्ष (आंध प्रदेश और तेलंगाना के लिए संयुक्त रूप से)	-
2025-2026	5,337 करोड़ रु.	6 गुना से अधिक

तेलंगाना राज्य में नए रेलपथों की कमीशनिंग/बिछाने का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	कमीशन की गई कुल लंबाई	कमीशन की गई औसत लंबाई
2009-14	87 कि.मी. (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए संयुक्त रूप से)	17.4 कि.मी. प्रति वर्ष
2014-24	650 कि.मी.	65 कि.मी. प्रति वर्ष (3 गुना से अधिक)

वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 में, तेलंगाना राज्य में 16,625 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 1088 किलोमीटर लंबाई की 13 परियोजनाओं (02 नई लाइन और 11 दोहरीकरण) को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान तेलंगाना राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुल 6,075 किलोमीटर लंबाई को कवर करने वाले 62 सर्वेक्षण कार्यों (19 नई लाइन और 43 दोहरीकरण) को स्वीकृति दी गई है।

गाड़ी सेवाओं के ठहराव के संबंध में अनुरोधों/अभ्यावेदनों की प्राप्ति सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे प्राप्त अनुरोधों/अभ्यावेदनों की जांच की जाती है और व्यवहार्य और औचित्यपूर्ण पाए जाने पर इस संबंध में समय-समय पर कार्रवाई की जाती है।

वर्तमान में, मंचेरियाल, मंदमारि और बेल्लमपल्ली स्टेशनों को निम्नलिखित गाड़ी सेवाओं द्वारा सेवित किया जा रहा है:-

क्रम सं.	स्टेशन	गाड़ी सेवाएं
1	मंचेरियाल	73 गाड़ी सेवाएं
2	मंदमारि	08 गाड़ी सेवाएं
3	बेल्लमपल्ली	52 गाड़ी सेवाएं

इसके अलावा, भारतीय रेल पर गाड़ी सेवाओं के ठहराव का प्रावधान करना यातायात औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता आदि के अध्यधीन एक सतत प्रक्रिया है।

\*\*\*\*\*